



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 21, 2014/वैशाख 1, 1936

No. 103]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 21, 2014/VAISAKHA 1, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना(निर्णायक समीक्षा)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2014

विषय:- चीन जन.गण में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित नायलान टायर कार्ड फेब्रिक (एनटीसीएफ) के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

सं. 15/32/2013-डीजीएडी. — यतः, समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण एवं क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन.गण में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित नायलान टायर कार्ड फेब्रिक (जिसे एतदपश्चात् सम्बद्ध वस्तु या एनटीसीएफ या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के आयातों पर मूल पाटनरोधी जांच प्रारंभ की थी और दिनांक 09 मार्च, 2005 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/20/2003-डीजीएडी के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी। तदनुसार चीन जन.गण (जिसे एतदपश्चात् सम्बद्ध देश कहा गया है) में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के सभी आयातों पर वित्त मंत्रालय की दिनांक 27 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना सं. 36/2005-सीमाशुल्क के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था। तत्पश्चात्, निर्दिष्ट प्राधिकारी को एसोसिएशन आफ सिन्थेटिक फाइबर इंडस्ट्री, नई दिल्ली से सम्बद्ध वस्तु पर उद्ग्रहित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसकी निरंतरता बनाए रखने तथा उसमें अगले पांच वर्षों तक इस आधार पर और वृद्धि करने कि चीन जन.गण से सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद पाटन की निरंतरता बनी हुई है तथा सम्बद्ध देश से पाटन के कारण घरेलू को लगातार क्षति सहन करनी पड़ रही है, का अनुरोध करते हुए एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदन पत्र उक्त अधिनियम की धारा 9क (5) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार एक आवेदनपत्र प्राप्त हुआ। यह भी दावा किया गया था कि सम्बद्ध देश के विरुद्ध इस उपाय की समाप्ति पर पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने तथा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एक पाटनरोधी निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ की और यह निष्कर्ष निकाला कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति अथवा दोनों की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने की सिफारिश करते हुए प्राधिकारी ने अंतिम निष्कर्ष दिनांक 31 मार्च, 2009

की अधिसूचना सं. 14/20/2008-डीजीएडी के तहत अधिसूचित किए थे और सम्बद्ध देश से आयातित सम्बद्ध वस्तु पर निर्णायक शुल्क दिनांक 29 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या 41/2009-सीमा शुल्क के तहत राजस्व विभाग द्वारा बढ़ाया गया था।

समीक्षा के लिए अनुरोध

2. यतः, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क का, यदि उसका पहले प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है तो, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति के पश्चात् प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

3. और उपर्युक्त उपबंध के होते हुए भी, ऐसे शुल्क की समाप्ति की तारीख से पहले युक्तियुक्त अवधि के अंदर घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए इस अनुरोध पर, कि क्या शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, प्राधिकारी को उसकी पुनरीक्षा करना अपेक्षित होता है।

4. और यतः उपर्युक्त उपबंधों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार एसोसिएशन आफ सिन्थेटिक फाइबर इंडस्ट्री, नई दिल्ली ने अपनी दो सदस्य कंपनियों अर्थात् मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड और मैसर्स सेन्चुरी एन्का लिमिटेड की ओर से विधिवत साक्ष्यांकित आवेदन के साथ प्राधिकारी से सम्बद्ध देश में उद्धवित अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर विगत में वित्त मंत्रालय की दिनांक 29 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना सं. 41/2009-सीमाशुल्क के तहत अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध किया और सम्बद्ध देश में उद्धवित अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता की मांग की। यह अनुरोध इस आधार पर आधारित है कि सम्बद्ध देश में उद्धवित अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु का पाटन सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद भी बना हुआ है और घरेलू उद्योग को सम्बद्ध देश से पाटन के कारण निरंतर क्षति बनी रही। आवेदक ने पुनः तर्क दिया है कि सम्बद्ध देश के विरुद्ध इस उपाय को समाप्त कर देने से सम्बद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

5. और, प्राधिकारी आवेदक द्वारा सम्बद्ध देश से पाटन तथा क्षति के दिए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर यह विचार करते हैं कि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क के लिए निर्णायक समीक्षा प्रक्रिया को प्रारंभ करना सम्बद्ध देश से पाटन को दूर करने के लिए उक्त शुल्क की निरंतरता बनाए रखने और यह जांच करने के लिए उपयुक्त होगा कि क्या शुल्क को समाप्त कर देने अथवा उसमें कुछ परिवर्तन कर देने से घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

घरेलू उद्योग एवं आधार

6. यह आवेदन पत्र एसोसिएशन आफ सिन्थेटिक फाइबर इंडस्ट्री, नई दिल्ली द्वारा अपनी दो सदस्य कंपनियों अर्थात् मैसर्स एस आर एफ लिमिटेड और मैसर्स सेन्चुरी एन्का लिमिटेड (जिन्हें एतदपश्चात् घरेलू उद्योग या आवेदक कहा गया है) द्वारा दायर किया गया है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन आवेदकों का कुल घरेलू उत्पादन में न केवल एक बड़ा हिस्सा है और न केवल वे घरेलू उद्योग बनते हैं बल्कि वे नियमालयी के आशय के अंतर्गत वर्तमान निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदन करने के आधार की सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

जांच शुरुआत

7. घरेलू उद्योग द्वारा समीक्षा की आवश्यकता के लिए अपेक्षित प्रस्तुत सभी साक्ष्यांकित प्रथम दृष्टया सकारात्मक साक्ष्यों के आधार पर स्वयं संतुष्ट होकर प्राधिकारी यह जांच करने के लिए कि क्या प्रभावी शुल्क की निरंतरता की आवश्यकता है और क्या उक्त शुल्क को समाप्त कर देने से सम्बद्ध वस्तु का पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति बने रहने की निरंतरता होने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार एक निर्णायक समीक्षा प्रारंभ करते हैं।

विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

8. वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण में उद्धवित अथवा वहां से निर्यातित नायलान टायर कार्ड फेब्रिक (एनटीसीएफ) है। सम्बद्ध वस्तु नायलान का एक फेब्रिक है जिसका उपयोग मुख्यतः टायर कार्ड के लिए होता है। एनटीसीएफ का अनुप्रयोग विभिन्न प्रकार आटोमोटिव टायरों जैसे बस और ट्रक टायरों, दुपहिया वाहनों के टायरों, साइकिल टायर, हल्के वाणिज्यिक वाहनों के टायरों, पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों के टायरों आदि में होता है। नायलान टायर कार्ड फेब्रिक का उत्पादन यार्न के विभिन्न डेनियर्स का प्रयोग करके होता है। इस फेब्रिक का प्रयोग टायरों को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस उत्पाद की बिक्री 'ग्रे फेब्रिक' और 'डिप्ड फेब्रिक' के रूप में की जाती है। यह विचाराधीन उत्पाद के केवल विभिन्न रूप हैं। भारतीय टायर उद्योग ग्रे और डिप्ड दोनों तरह के फेब्रिक की खरीद करता है। एनटीसीएफ के सभी उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंदर आते हैं और उन्हें सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29, सीमाशुल्क उपशीर्षक संख्या 5902.10.00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि यह

वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। यह विगत में आयोजित की गई जांच की एक निर्णायक समीक्षा होने के कारण, इसमें विगत जांच के विचाराधीन उत्पाद के दायरे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

9. इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और सम्बद्ध देश से भारत में आयातित सम्बद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत समान वस्तु है; यह कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु और सम्बद्ध देश से आयातित सम्बद्ध वस्तु अनिवार्य उत्पाद विशिष्टताओं जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी कार्यों एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण वितरण एवं विपणन और वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय है; यह कि उपभोक्तागण दोनों का प्रयोग अंतःपरिवर्तनीय रूप से कर सकते हैं और कर रहे हैं और यह कि दोनों वाणिज्यिक रूप से एवं तकनीकी रूप से प्रतिस्थानीय हैं। जांच के पश्चात् प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु, सम्बद्ध देश से आयातित सम्बद्ध वस्तु के समान वस्तु है।

प्रक्रिया

10. यह जांच यह निर्धारित करेगी कि क्या इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या पाटन को दूर करने के लिए शुल्क का सतत अधिरोपण अनिवार्य है और यदि शुल्क को हटा दिया जाता है या उसमें कुछ अंतर कर दिया जाता है तो क्षति बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

- i. यह समीक्षा दिनांक 31 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. 14/20/2009-डीजीएडी और 29 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना सं. 41/2009 सीमाशुल्क के सभी पहलुओं को कवर करेगी।
- ii. इस समीक्षा जांच में अंतर्ग्रस्त देश चीन जन.गण है।
- iii. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) अक्टूबर, 2012 से सितम्बर, 2013 है और क्षति विश्लेषण के लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा जांच की अवधि के आंकड़ों पर भी विचार किया जाएगा।
- iv. नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबन्ध इस समीक्षा में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

11. सम्बद्ध देश के निर्यातकों तथा उसकी सरकार को भारत स्थित उसके राजदूतावासों के जरिए और भारत में इस उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से सभी संगत जानकारी दर्ज करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत करने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा नं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

12. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे उल्लिखित समय सीमा के अंदर विहित स्वरूप और ढंग से जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी अन्य पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तुत करना भी अपेक्षित होगा।

समय-सीमा

13. वर्तमान जांच से संबंधित किसी सूचना को लिखित रूप में प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे कि यह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी से इस वर्तमान जांच की सूचना की पत्र की तारीख से 40 दिनों (चालीस दिनों) से अनधिक समय में पहुँच जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के अंदर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

14. वर्तमान मामले में सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें और घरेलू उद्योग के आवेदनपत्र पर पर प्राधिकारी से इस वर्तमान जांच की सूचना की पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के अंदर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें। यह सूचना हार्ड कापी और साफ्ट कापी दोनों रूपों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

.15 प्रश्नावली प्रत्युत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई प्रस्तुति करने वाले पक्षकारों से इसे दो (अनुबंध सहित / परिशिष्ट इससे संलग्न) पृथक सेटों में यदि इसके किसी भाग पर "गोपनीयता" का दावा किया जाता है, फाइल किया जाना अपेक्षित है :-

एक सेट (क) गोपनीय के रूप में शीर्षक), पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका, आदि सहित चिह्नित किया गया हो (, और

शीर्षक) पनीय के रूप में दूसरा सेट अगो (ख), पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका, आदि सहित चिह्नित किया गया हो । (

.16 "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" की प्रस्तुति को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" रूप में स्पष्ट चिह्नित : ति प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय रूप में समझी जाएगी और प्राधिकारी इस बात कन के बिना की गई प्रस्तुतियां जाना चाहिए। ऐसे चिह्नां ति का निरीक्षण करनेतंत्र होंगे कि ऐसी प्रस्तुत के लिए स्वके लिए वह अन्य पक्षकारों को अनुमति प्रदान करें। दोनों संस्करणों की सॉफ्ट कापी भी प्रत्येक के पांच सेटों में (5), हार्ड कापी के साथ, प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा ।

.17 गोपनीय संस्करण में ऐसी सभी सूचनाएं समाविष्ट होंगी जो प्रकृति में गोपनीय हों और सूचना जिसके बारे में ऐसी अथवा अन्य/ सूचना की आपूर्ति करने वाला गोपनीयता के रूप में दावा करता हो। सूचना, जिसकी प्रकृति में गोपनीयता के रूप में दावा किया जाता है अथवा वह सूचना, जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, के लिए, सूचना आपूर्तिकर्ता से प्राप्त सूचना कि ऐसी सूचना क्यों प्रकट नहीं की जा सकती है, के साथ एक उचित कारण विवरण दिया जाना अपेक्षित है ।

18. अगोपनीय संस्करण सूचना अनुक्रमित अथवा रिक्त किए गए और जिस पर गोपनीयता का (व न होयदि अनुक्रमणिका सम्भ) दावा किया गया हो, के आधार पर सार रूप में की गई गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना अपेक्षित है । अगोपनीय सार इतने विस्तृत रूप में हो कि उससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार की पर्याप्त समझ प्राप्त हो सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि उसका सार प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

19. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच करने के पश्चात् गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए किया गया अनुरोध वांछित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता उस सूचना को सार्वजनिक करने का या तो इच्छुक नहीं है या उसका सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करना नहीं चाहता है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकते हैं।

20. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता की दावे के संबंध में सद्कारण के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

21. प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लिए जाने पर प्राधिकारी ऐसी सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किए बिना किसी भी पक्षकार को उस सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

22. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुरूप कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठयुक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।

असहयोग

23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार किसी सूचना की पहुंच तक मनाही करता है और युक्तिसंगत अवधि के अंदर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं कराता है अथवा जांच में भारी व्यवधान उत्पन्न करता है तो प्राधिकारी उनको उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को समुचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2014

(SUNSET REVIEW)

Subject: Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed on imports of Nylon Tyre Cord Fabric (NTCF), originating in or exported from China PR.

No 15/32/2013-DGAD.— Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the AD Rules), the

Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated the original anti dumping investigation in respect of the imports of Nylon Tyre Cord Fabric (hereinafter referred to as the subject goods or NTCF or product under consideration) originating in or exported from China PR and definitive anti dumping duty was recommended vide Final Findings Notification No. 14/20/2003-DGAD dated 9th March, 2005. Accordingly, definitive anti dumping duties were imposed vide Ministry of Finance Notification No 36/2005-Customs dated 27th April, 2005 on all imports of the subject goods originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country). Thereafter, the Designated Authority, in terms of section 9A (5) of said Act, received a substantiated application from the Association of Synthetic Fibre Industry, New Delhi, requesting for review and continuation with enhancement of the anti-dumping duties levied on the subject goods, for another five years on the grounds that the dumping had continued in spite of imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from China PR and the domestic industry continued to suffer injury on account of dumping by the subject country. It was also claimed that expiry of measure against the subject country would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The Designated Authority initiated the Sunset Review anti-dumping investigations and concluded that the expiry of anti dumping duty would lead to continuation or recurrence of dumping, injury or both. The Final Findings recommending continuation of anti dumping duty were notified by the Authority on 31st March, 2009 vide Notification No. 14/20/2008-DGAD and definitive duties on the subject goods imported from subject country were extended by the Department of Revenue vide Notification No. 41/2009-Customs dated 29th April, 2009.

Request for Review

2. Whereas, in terms of the Customs Tariff Act, 1995, the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition.
3. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. And, whereas, in terms of the above provisions, the Association of Synthetic Fibre Industry, New Delhi, on behalf of two of its member companies, namely, M/s SRF Ltd and M/s Century Enka Ltd has approached the Authority with a duly substantiated application requesting for sunset review of the anti-dumping duties earlier imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries vide Ministry of Finance Notification No 41/2009-Customs dated 29th April, 2009 and seeking the continuation of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country. The request is based on the grounds that dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country has continued in spite of the imposition of anti-dumping duties on the import of the subject goods from the subject country and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject country. The applicant has further argued that the expiry of the measure against the subject country would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
5. And, the Authority, on the basis of prime facie evidence of dumping and injury to the domestic industry given by the applicant, considers that initiation of sunset review proceedings for the anti-dumping duties in force would be appropriate to examine the need for continuation of such duties to offset dumping from the subject country and to examine as to whether the injury to the domestic industry is likely to continue or recur if the duties were removed or varied.

Domestic Industry and Standing

6. The application has been filed by the Association of Synthetic Fibre Industry, New Delhi on behalf of two of its member companies, namely, M/s SRF Ltd and M/s Century Enka Ltd (hereinafter referred to as the applicant or the domestic industry) who have provided the relevant information. As per the information available, the applicants account for a major proportion in Indian production of the subject goods and, therefore, constitute domestic industry within the meaning of the Rules and has the standing to file the application within the meaning of the Rules.

Initiation

7. Having satisfied itself on the basis of the positive prima facie evidence submitted by the domestic industry substantiating significant dumping margin and the need for a review in respect of the subject country, the Authority hereby initiates a Sunset Review in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules, to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duties would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

8. Product under Consideration and Like Article

9. The product under consideration in the present review investigation is Nylon Tyre Cord Fabric (NTCF) originating in or exported from China PR. The subject good is a fabric of nylon, meant largely for tyre cord. NTCF finds application in different kinds of automotive tyres such as bus & truck tyres, two wheeler tyres, cycle tyres, light commercial vehicles tyres, animals driven vehicles etc. Nylon Tyre Cord fabric is produced using different deniers of yarn. The fabric is used for reinforcement of tyres. The product is sold as "Grey fabric" and also "Dipped fabric". These are only different forms of the product under consideration. The Indian Tyre Industry is buying both grey and dipped fabric. All types of NTCF are within the scope of the product under consideration and are classified under Chapter 59, Custom subheading No. 5902.10.00 of the Customs Tariff Act. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. This being sunset review of investigations previously conducted, there is no change in the scope of product under consideration from the previous investigations.

10. Further, the applicant submitted that the product manufactured by the domestic industry and the subject good imported into India from the subject country are like articles within the meaning of the Anti-dumping Rules; that there is no known difference between the subject goods imported from the subject country and that produced by the domestic industry; that the subject good produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods; that the consumers can use and are using the two interchangeably and that the two are technically and commercially substitutable. After examination, the Authority concludes that the subject good produced by the domestic industry are like article to that imported from the subject country.

Procedure

11. The investigation will determine as to whether the expiry of the measures would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine as to whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duties were removed or varied.

- i. The review will cover all aspects of the Notification No. 14/20/2008-DGAD dated 31st March, 2009 and the Notification No. 41/2009-Customs dated 29th April, 2009.
- ii. The country involved in this review investigation is China PR.
- iii. The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is from October 2012 to September 2013 and for the injury analysis, data of the previous three years, viz., 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the POI will be considered.
- iv. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

11. The exporters in the subject country, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Room No 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011

12. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

13. Any information relating to the present review should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of the letter from the Authority communicating the initiation of this investigation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

14. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of the letter from the Authority communicating the initiation of this investigation. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

15. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

- (a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- (b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

16. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

17. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

18. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

19. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

20. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

21. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

22. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

23. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J S DEEPAK, Designated Authority